

लापरवाही से बदल रही नदी की धारा, अफसरों को नहीं परवाह

बारिश में शहर के लिए मुसीबत बनेगी जीवन दायिनी, वैनगंगा नदी में नियमों और अधिकारों का अतिक्रमण कर किया जा रहा खनन

सिवनी नवभारत। जिले के छपारा तहसील मुख्यालय के किनारे से बहने वाली जिले की जीवनदायिनी **वैनगंगा नदी** से **सिल्ट** निकालने का आदेश अब विभाग के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में **छपारा शहर** के लिए भी जलभराव क्षमता बढ़ाने का यह कथित आदेश परेशानी का सबब बन सकता है। मानसून के मुहाने पर खड़े शहरी अब आने वाले दिनों की चिंताओं को लेकर परेशान हैं। डूब क्षेत्र में आने वाले छपारा में इस खनन से अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह बिना किसी व्यवस्थित देखरेख के बेतरतीब तरीके से नदी को छलनी किया जा रहा है वह भी सवालों के दायरे में है। पर्यावरण को होने वाली संभावित क्षति को लेकर अब पर्यावरण प्रेमी भी इस मामले को सभी संभव मंत्रों पर ले जाने की बात कह रहे हैं। वहीं अधिकारी अपनी खामियों को छिपाने के लिए अलग-अलग तर्क दे रहे हैं।

छपारा मुख्यालय के किनारे वैनगंगा नदी बहती है। मई माह की 11 तारीख को मध्यप्रदेश गौण कानून अधिनियम 1996 के प्रावधान अनुसार छपारा नगर परिषद के सीएमओ को सिंचाई

विभाग के कार्यपालन यंत्री पीएन नाग ने लोक प्रायोजन के चलते सिल्ट (गाद) निकालने की अनुमति दी। जिसके बाद नगर परिषद के द्वारा छपारा नगर के किनारे से बहने वाली वैनगंगा नदी में सिल्ट की खुदाई शुरू कर दी गई। आलम यह रहा कि दर्जनों ट्रकों, डंपर और कई जेसीबी के जरिए खुदाई शुरू कर दी गई। इस दौरान बेतरतीब तरीके से नदी में खनन शुरू कर दिया गया। काफी सारी मिट्टी बाहर पहुंचा दी गई वहीं कई डंपर मिट्टी को नदी के एक किनारे पर सिंचाई विभाग की जमीन पर जमा कर रख दिया गया। जिससे नदी का एक किनारा काफी ऊंचा और दूसरा निचला हो गया है। इसके साथ ही नदी के किनारे को पाटकर वहां पर सिल्ट जमाई जा रही है। छपारा के बीच से निकलने वाले एक नाले की दिशा भी मोड़ दी गई है और वैनगंगा की भी दिशा में बदलाव किया जा रहा है। वैनगंगा में सिल्ट निकाले जाने की अनुमति को लेकर मंशा पर कई सवाल उठ रहे हैं। वैनगंगा से निकाली जाने वाली सिल्ट का कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा है। कितने, किसके डंपर खनन कर रहे हैं। इसकी कोई सूची नहीं बनाई जा



नदी की मुड़ रही है दिशा

छपारा में पुल और घाट के पास एक स्थान पर बड़ी मात्रा में नदी से निकाली जा रही मिट्टी को जमा किया जा रहा है। इससे नदी की दिशा मुड़ जाने की आशंका बनी हुई है। एक ओर का तट ऊंचा हो जाने से दूसरी ओर के खेतों और घरों में पानी घुसने की आशंका है। वहीं नदी में मिलने वाले एक नाला की भी दिशा मोड़ी जा रही है। जिससे जलभराव के दिनों में पानी शहर में घुसने की आशंका है।

रही है। इसके साथ ही खनन किस स्थान पर, कैसे और कितना किया जाएगा इसकी भी निगरानी नहीं रखी जा रही है। नदी के किनारे सिल्ट को डंप किया जा रहा है। जिससे भविष्य में अतिक्रमण की संभावना बनी हुई है। जिस बड़े पैमाने में वैनगंगा

नदी में सिल्ट के नाम पर उत्खनन किया जा रहा है उसकी कोई निगरानी न तो सिंचाई विभाग और ना ही नगर परिषद के द्वारा की जा रही है। कितने वाहन इस काम में लगे हैं, कितनी अबतक खुदाई हो चुकी है इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। आमतौर पर ये सिल्ट

इसलिए उठ रहे हैं सवाल

इस पूरी कार्रवाई में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि छपारा का यह वैनगंगा तट डूब क्षेत्र में आता है। गोंडवाना शासन काल की बनी गद्दी लगभग आठ महीने डूब में रहती है। इस तरह के बांध अक्सर आगामी एक सौ बरसों की योजना को लेकर बनाए जाते हैं। ऐसे में डूब क्षेत्र से सिल्ट निकाले जाने की अनुमति देने की योजना शासन स्तर से बनाई जाती है। विभाग के अधिकारी जिन नियमों के आधार पर अनुमति की बात कर रहे हैं वे खनिज विभाग के लिए हैं। वहीं गौण खनिज के आधार पर सिल्ट की अनुमति दी गई है जबकि यह भूमि आर्द भूमि के तहत आती है। सिल्ट को एक स्थान पर एकत्र किए जाने को लेकर अधिकारी जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। जरूरी है कि इस मामले पर आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएं नहीं तो आने वाले दिनों में आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।

इनका कहना है

खनन की अनुमति नगर परिषद के आवेदन पर दी गई है। सिल्ट निकालकर कहां डंप की जा रही है इसकी जानकारी नहीं है। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी है इस कारण वहां कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। यदि भविष्य में अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

—पीएन नाग, कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग

मैंने हाल में ही ज्वानि किया हूं। इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं है। आपके द्वारा सज्ज्ञान में लाने के बाद मैं खुद मौके पर जाकर मुआयना करूंगा। यदि कुछ गलत हो रहा है तो दोषियों पर कार्रवाई के लिए अनुसंधान की जाएगी।

—उदय सिंह परते, सीईई, सिंचाई विभाग

काफी उपजाऊ होती है जिसे किसानों के खेतों में दिया जाना चाहिए लेकिन यहां पर निकाली जा रही सिल्ट को एक स्थान पर जमा किया जा रहा है। सिंचाई विभाग की इस जमीन में पहले से ही अतिक्रमण कर कई पक्के निर्माण

कार्य किए जा चुके हैं लेकिन बावजूद इसके विभाग की चुप्पी सवाल खड़े करती है। पिछले दिनों खुदाई करते हुए कुंभकारों के लिए सुरक्षित भूमि पर भी जेसीबी पहुंच गई थी जिसके बाद काफी विवाद की स्थिति बनी थी।

आगामी पर्वों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित

सिवनी नवभारत। आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा सहित शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, विभिन्न धर्मों के गणमान्य नागरिक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने जुलूस मार्गों पर एंबुलेंस एवं चिकित्सकीय टीम को उपलब्धता सुनिश्चित करने, मार्गों की साफ-सफाई कराने तथा बिजली के तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना न रहे।

बैठक में सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा अफवाह फैलाने वाली पोस्ट न करें और न ही उन्हें साझा करें। प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक सामग्री पर सतत निगरानी रखी जाएगी।



मोहरंग को लेकर बनी सहमति

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी मोहर्रम पर्व के दौरान ताजिया एवं अखाड़ा जुलूस पूर्व निर्धारित मार्गों से ही निकाले जाएंगे। सभी से अपील की गई कि जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे का उपयोग न किया जाए तथा किसी भी धार्मिक स्थल के सामने ऐसे गीत या संगीत का प्रसारण न हो, जिससे किसी अन्य धर्म या समुदाय की भावनाएं आहत हों। ताजिया विसर्जन केवल प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थलों पर किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही विसर्जन स्थल दल सागर में समुचित प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

एक नजर में

साहू (गोल्हानी) समाज का मिलन एवं पदभार ग्रहण 23 को

लखनादौन। 23 जून मंगलवार को नगर लखनादौन में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। मिलन एवं पदभार ग्रहण समारोह में छिंदवाड़ा सांसद विवेक (बीटी) साहू, एवं प्रभुनाथ साहू एवं महावीर जबलपुर के मुख्य अतिथ्य में विधायक सिंगरीली रामनिवाहा शाह एवं पूर्व तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष रवि करण साहू विशिष्ट अतिथ्य एवं साहू समाज के जिला अध्यक्ष सिवनी गुलाब साहू अध्यक्षता करेंगे। जानकारी में प्राप्त हुआ है कि बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर जिलों से भी अतिथियों का आगमन होगा। इस मिलन एवं पदभार ग्रहण समारोह में छपारा धनोरा घंसीर लखनादौन केवलारी सिवनी बरघाट के स्वजातीय बंधुओं को भी आमंत्रित किया गया है। विगत माह लखनादौन नगर गोल्हानी साहू समाज का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध अनिल कुमार गोल्हानी (सिहोरा वाले) को अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष आनंद कुमार गोल्हानी कैलाश गोल्हानी एवं संजय कुमार गोल्हानी, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोल्हानी सचिव जगदीश प्रसाद गोल्हानी सह सचिव जगदीश साहू को चुना गया है। 23 जून मंगलवार को दोपहर 1:00 से नगर के हनुमान मंदिर के समीप स्थित सात फेरे लान में बड़ी धूमधाम एवं भव्यता के साथ मिलन समारोह आयोजित होने जा रहा है जिसमें अतिथियों के द्वारा सभी पदाधिकारी को पदभार ग्रहण कराया जाएगा।



विधायक किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में हुए सम्मिलित

सिवनी। दिनेश राय मुनमुन ने शनिवार, को किसान सम्मान निधि हस्तान्तरण, प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में सहभागिता की। वह कार्यक्रम सिवनी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में राशि का वरुंअल हस्तान्तरण किया गया। इसके उपरांत प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक दिनेश राय मुनमुन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और कृषि केवल व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी किसान परिवार से आते हैं और खेती की चुनौतियों तथा बदलावों को कड़ीब से समझते हैं। उन्होंने बताया कि तकनीकी विकास के कारण आज कम भूमि में भी अधिक उत्पादन संभव हो सका है, जिससे किसानों की समृद्धि बढ़ी है। उन्होंने कहा कि खेती में प्रगति के साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है और इसका असर स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित रखने का आह्वान किया।



प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों में

हितग्राहियों का कराया गया गृह प्रवेश एवं भूमिपूजन

सिवनी। 19 जून को नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा निकाय क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर वार्ड क्रमांक 22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही श्रीमति मेहती बाई रजक, श्रीमति गुलाबा बाई यादव, श्रीमति प्रेमा बाई के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित 03 मकानों में उनका गृह प्रवेश करवाया गया साथ ही बिंदु गोसाईं के मकान का भूमिपूजन करवाया गया। गृह प्रवेश के दौरान निकाय के सहायक उंत्री श्रीमति देवेश्वरी धुवे, सहायक लिपिक शुभम मालवी द्वारा पात्र हितग्राहियों के गृह प्रवेश पर उन्हें बधाई दी गई।

लापरवाही

हॉस्टल अधीक्षक मयूर महाजन भी अपने कार्य के प्रति नहीं दिख रहे जिम्मेदार, रसोईये ने अपनी जगह लगा दिया मजदूर

नया शैक्षणिक सत्र आरंभ छात्रावास से रहते है, कर्मचारी नदारद...

उत्तली नवभारत। सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाले विकासखंड केवेलारी के उगली के अंतर्गत निकट ग्राम मोहबरां सोनियर आदिवासी बालक छात्रावास मोहबरां में नए शैक्षणिक सत्र का आरंभ हो चुका है, और स्कूलों में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम चालू हो गया है नए सत्र के प्रवेश और अन्य गतिविधियां संचालित होने भी लगी है।

लेकिन दुर्भाग्य का विषय छात्रावास में अधीक्षक, रसोईया, जलवाहक व चौकीदार सभी पूरा स्थल मौजूद होने के बाद भी पिछले सत्र की परीक्षा अवधि समाप्ति के बाद से आज दिवस तक रसोईया अरुण चंदौल जो केवल औपचारिकता के आधार पर



रसोईया के पद पर होने के बाद, अपने हॉस्टल में औपचारिका अदा करते हैं, इन्होंने अपने कार्य में बाधा ना आए इसलिए एक मोहबरां के संतोष रांहंडालें को मजदूरी में अपने कार्य पर रख लिया था, जिन्हें रुपए 5000 मासिक भुगतान के आधार पर रखा गया था, जिसको उसकी मजदूरी का भुगतान भी

बकाया है, दूसरी गंभीर बात हॉस्टल अधीक्षक मयूर महाजन यह भी अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार दिखाई नहीं पड़ते, आए दिन जिला मुख्यालय और अन्य दूसरी गतिविधियों में व्यस्ततम ही दिखाई देते हैं, अगले कर्मचारी मोहबरां के ही एक सातुलेजी हैं, जो बतौर चौकीदार है, और आगामी दो महिने

बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे केवल एक जलवाहक लक्ष्मी रांहंडाले से जब पत्रकारों के दल ने गत दिवस हॉस्टल का निरीक्षण किया तो पता चला कि रसोईया पद पर अरुण चंदौल ने 16 जून को हॉस्टल आकर साफ सफाई साथ में करेंगे ऐसा बोला था, लेकिन आज 20-21 तारीख हो गई है उनका कोई अता पता नहीं है। इस संदर्भ में हॉस्टल अधीक्षक से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नियमित सभी कर्मचारी हॉस्टल आते हैं, हॉस्टल की गंभीर स्थिति यह है, कि नए प्रवेश के लिए प्रबंधन के पास वहां पर फार्म उपलब्ध नहीं है, बिजली व्यवस्था हॉस्टल की ठप्प पड़ी है, क्योंकि छात्रावास में विद्यालय को घर जैसा माहौल प्रदान किया जाए



परिस्थितियां हैं जिसके कारण वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा अधिकारों एवं भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की अशंका व्यक्त की जा रही है। यह निर्णय भारतीय विधिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के स्थापित सिद्धांत जिसमें अधिसूचना उसके प्रवर्तन तिथि से प्रभावित होती है के विरुद्ध

है। दशकों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव, कार्य कुशलता एवं योगदान को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। सांसद एवं केंद्र सरकार आवश्यक विधायी अथवा नीतिगत हस्तक्षेप कर शिक्षक वर्ग को उचित संरक्षण प्रदान कर सकती है। इस निमम के लागू होने से न्याय ,समानता एवं विधिक

निष्पक्षता के सिद्धांतों की अवहेलना हो रही है।

शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि संघ को विश्वास है कि राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस शिक्षक वर्ग के साथ भारत सरकार संवेदनशीलता, दूरदर्शिता एवं न्याय पूर्ण दृष्टिकोण का परिचय देगी। ज्ञापन के दौरान संघ के जिला सचिव संतोष सूर्यवंशी, कोषाध्यक्ष के एल पटले, उपाध्यक्ष सचिन जैन, एवं विभिन्न विकास खंडों से मनोज कश्यप, परशुराम सनोडिया, रघुनाथ चौकसे, उमेश उडके , राम ठाकुर श्रीमती सरोज मरावी, श्रीमती मेडम धुर्वे, जैस पटले ,श्री हरिखेड़े, गम्फार खान अजय यादव एवं बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि पदाधिकारी उपस्थित है।

महाराणा प्रताप जयंती पर वीरांगनाओं ने किया माल्यार्पण,

बरघाट। अंतरराष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा, सिवनी द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर बरघाट स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपस्थित वीरांगनाओं एवं समाजजनों ने महाराणा प्रताप के अद्वितीय शौर्य, त्याग, राष्ट्रभक्ति एवं स्वाभिमान को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाज की एकता पर बल देते हुए सभी क्षत्रिय परिवारों से संगठित रहने एवं महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और राष्ट्रभेम की प्रेरणा देता है, जो आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा की प्रदेश महासचिव सविता गौतम, जिला अध्यक्ष खुशहाल चौहान, जिला संरक्षक शोभा राजपूत, उपाध्यक्ष, संध्या राजपूत एवं आकांक्षा सेगर सहित अन्य की उपस्थिति रही।

10 लाख का खेल मैदान या भ्रष्टाचार का मैदान?

सिवनी/कुरई नवभारत। जनपद पंचायत कुरई अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछुआमाल में लगभग 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित खेल मैदान को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और खर्च की गई राशि पर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय तकनीकी एवं वित्तीय जांच की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि खेल मैदान निर्माण के लिए लाखों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद धरातल का खेल अपेक्षित स्तर का दिखाई नहीं देता। उनका कहना है कि निर्माण की वास्तविक स्थिति और स्वीकृत राशि के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

मामले को लेकर जब संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। इससे ग्रामीणों के मन में संदेह और गहरा गया है।

उनका कहना है कि यदि विकास कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ हुए हैं तो संबंधित विभाग को सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। जनपद पंचायत कुरई के अध्यक्ष लोचन सिंह मर्सकोले और उपाध्यक्ष हरदीप सिंह भाटिया ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने संबंधित उपयंत्री के कार्य व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग प्रशासन से की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि खेल मैदान सहित पंचायत में हुए सभी विकास कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय जांच कराई जाए। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं। बिछुआमाल का यह मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों के उम्मीद है कि प्रशासन शीघ्र हस्तक्षेप कर मामले की जांच कराएगा।